THE

PARLIAMENTARY DEBATES

OFFICIAL REPORT

IN THE TWENTY-FOURTH SESSION OF THE RAJYA SABHA

Commencing on the 9th February, 1959

RAJYA SABHA

Monday, the 9th February 1959

The House met at thirty minutes past twelve of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

PRESIDENT'S ADDRESS LAID ON THE TABLE

SECRETARY: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 9th February, 1959.

(Text of the President's Address in (Hindi)

संसद् के सदस्यगण, ससद् के नये सत्र का भार संभालने के समय आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं ।

२. दूसरी पंच-वर्षीय योजना का तीसरा वर्ष समाप्त होने जा रहा है । अपने गत फरवरी के अभिभाषण में, मैंने आपका ध्यान हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले दबावों की ओर आकर्षित किया था । मैंने यह कहा था कि मेरी सरकार की यह उत्कट इच्छा है कि इन कठिनाइयों के कारण हमारे विकास के कार्यक्रम में कोई बाधा नही आनी चाहिये और पुनर्विचार, कार्य-प्रणाली में संशोधन और योजनानुसार साधनों को जुटा कर इन कठिनाइयों पर काबू पाना चाहिये ।

३. गत वर्ष मई में और फिर नवम्बर में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दूसरी योजना से सम्बन्धित साधनों के प्रश्न पर, उत्पादन की समस्या पर और क्रमिक विकास पर विचार किया, और उसने यह फैसला किया कि योजना का कुल खर्चा ४५०० करोड़ होना चाहिये और इसे बचत और साधनों में वृद्धि द्वारा प्राप्त करना चाहिये ।

४. मेरी सरकार की आर्थिक नीति का यह लक्ष्य है । विदेशी मुद्रा के व्यय और भावी उपयोग को कम करने, कीमतों के बढ़ाव को रोकने और विदेशों में होने वाली आय को बढ़ाने के लिये उपाय अपनाये गये है । बहुत सी चीजों पर से निर्यात कर हटा लिया गया है या कम कर दिया गया है और निर्यात के कोटे को बढ़ा दिया गया है । विदेशी व्यापार सम्बधी नियमावली पर पुनर्विचार के परिणाम-स्वरूप अगस्त १९५८ में २०० वस्तुओं पर से निर्यात कन्ट्रोल हटा लिया गया और जिन चीजों पर निर्यात का प्रतिबधं था उनकी सूची में काट छांट की गई ।

५. अस्थाई कठिनाई पर पार पाने की दृष्टि से मेरी सरकार को विदेशों से ऋण तथा सहायता आदि प्राप्त करने में सफलता मिली है । अधिक सहायता के लिए बात-चीत जारी है । यह सहायता और ऋण जो हमें विदेशों से मिले हैं और जिनके लिए मेरी सरकार और हमारे देशवासी आभारी

हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक शर्तों से मुक्त हैं। भावी सहायता के लिए बातचीत भी इसी आधार पर की जायेगी।

६. हमारी दूसरी योजना देश के आर्थिक विकास के व्यापक कार्यक्रम का एक अंग है। जो कदम हम इस समय उठा रहे हैं, वे योजनाबद्ध सम्पन्नता के लम्बे और कष्टप्रद मार्ग में पड़ाव मात्र हैं। मेरी सरकार ने योजना आयोग के द्वारा तीसरी योजना के सम्बन्ध में अध्ययन तथा सोच-विचार आरम्भ कर दिया है। आशा है कि हम मौलिक उद्योगों, कृषि उत्पादन और ग्रामीण उन्नति के सम्बंध में तीसरी योजना के अन्त तक भावी विकास की नींव रख चुकेंगे, जिसके फलस्वरूप आत्मनिर्भर और स्वाश्रयी आर्थिक व्यवस्था का जन्म हो सकेगा।

७. आयोजन एक राष्ट्रीय प्रयास है जिसके लिए हर कदम पर राष्ट्र भर का सहयोग और सामूहिक प्रयत्न अपेक्षित हैं। इसलिए मेरी सरकार ने संसद् के भीतर और बाहर सभी लोगों से यह याचना की है कि इस विषय में सब लोग रचनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे, भले ही वे आलोचनात्मक हों। इस काम के लिये मेरे प्रधान मंत्री और योजना आयोग सभी दलों का सहयोग चाहते हैं।

८. हमारा विचार है कि इस वर्ष के अन्त तक तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार कर ली जाये। जब रूपरेखा विचार विमर्श के बाद अनुमोदित हो जाये, तब केन्द्र और राज्यों की योजनाओं पर विस्तार से सोच विचार शुरू किया जाये। जिन लक्ष्यों को हमने स्वीकार किया है उनमें से प्रधान यह हैं :—राष्ट्रीय आय में ठोस वृद्धि, शीघ्रतापूर्ण औद्योगिकरण, बड़े पैमाने पर रोजगार का विस्तार और आमदनी तथा सम्पत्ति की असमताओं में कमी। सरकार घरेलू और छोटे उद्योगों को भी यथापूर्व सहायता देती रहेगी। विकास के काम में अभी तक हमें जो सफलता मिली है उसे हमें बनाये रखना है और उसकी गति को तेज करना है।

९. हमारी आर्थिक व्यवस्था के नियमन के लिए जो बातें सब से ज़रूरी हैं उनमें सर्वप्रथम खाने पीने की चीजें और इन चीजों के भाव हैं। हमारे आयोजन और उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक दूसरी बातें अधिकतर इन्हीं पर निर्भर करती हैं, जैसे विकास के काम के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि, देने-पावने के सन्तुलन की स्थिति, देश के अन्दर मूल्य स्तरों की स्थिरता और मुद्रा बाहुल्य की प्रवृत्तियों की यथासमय रोक-थाम।

१०. फसलों को भारी नुक्सान पहुंचने के बाद १९५८ के आरम्भ में अनाज के बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिए मेरी सरकार ने उस वर्ष के पहले ११ महीनों में २७ लाख ४० हज़ार टन अनाज विदेशों से मंगाया, देश के अन्दर अनाज के यातायात का नियमन किया और, और लोगों को अनाज उपलब्ध करने के लिए सस्ते दामों की दुकानें खोली गईं। अनाज के व्यापारियो द्वारा अत्यधिक संचय की रोकथाम के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा उधार दिये जाने की नीति कड़ी कर दी।

११. इस दिशा में खुराक के मामले में आत्मनिर्भरता ही हमारी समस्या का संतोषजनक हल है। भरपूर प्रयत्न, खेती के सुधरे हुए तरीकों का अपनाया जाना और भूमि सम्बन्धी कानून में आवश्यक सुधार, जिससे कि खेती का काम लाभदायक हो, ये बातें उत्पादन में वृद्धि के लिए अनिवार्य रूप से ज़रूरी हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार भूमि सम्बन्धी कानून में सुधार और सहयोग तथा ग्रामों को व्यापक कार्यक्षेत्र देकर प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी।

१२. पिछले साल की अपेक्षा १६५६–६० में फसलों की स्थिति आशाजनक है। इस वर्ष हम पर प्रकृति की कृपा रही है और खाद्य तथा व्यापारी फसलें दोनों ही उत्साह-वर्द्धक हैं। हमारी चावल की फसल बहुत बढ़िया रही और उसके कारण चावल के दामों में पहले ही कमी हो गई है। हमारा विचार है बड़े पैमाने पर चावल का संचय किया जाये और शासकीय व्यापार का विस्तार किया जाये। गेहूं और चने के भाव ऊंचे चढ़ गए हैं, किन्तु इस समय के लक्षणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रबी की फसल भी अच्छी होगी। भरपूर खेती के आन्दोलन, सिंचाई के छोटे साधनों पर अधिक जोर, सिंचाई के मौजूदा साधनों का पूरा उपयोग, सुधरे हुए बीज के वितरण के लिये अधिक केन्द्रों की स्थापना, खेती के सुधरे हुए तरीकों को अपनाने की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति और भूमि के संरक्षण-सम्बन्धी कार्यक्रम का विस्तार—इन सब बातों के कारण ही खेती के क्षेत्र में और विशेषकर प्रधान फसलों के बारे में स्थिति आशाजनक हो पायी है।

१३. सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ही यह निर्भर करता है कि हमारे देहातों में रहने वाली करोड़ों जन-संख्या के लिये सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र का विस्तार हो और वह प्रणाली कार्यान्वित हो। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तीन लाख गांव आ चुके है जिनकी जन-संख्या साढ़े सोलह करोड़ के करीब है। इस कार्यक्रम में लोगों का अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिये आवश्यक उपाय काम में लाये जा रहे है। ग्राम पंचायत को, जो हमारे लोकतन्त्र की आधारभूत इकाई है, अधिक साधन और अधिकार दिये जा रहे हैं। देहातों में सहयोग समितियां स्थापित और उन्नत की जा रही है जिससे कि सारा ग्रामीण क्षेत्र उनके अन्तर्गत आ जाये।

१४. औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, किन्तु कुछ उद्योगों को, खासकर सूती कपड़े के उद्योग को, ठेस पहुंची है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में जिन उद्योगों मे उत्पादन बहुत बढ़ा है, वे हैं मशीनी औज़ार, पैनीसिलीन, कृमिनाशक औषधियां, कागज और गत्ता, डीज़ल इन्जन, बिजली के मोटर, सलफ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, टायर, सिलाई की मशीनें, बाइसिकल और बिजली के पंखे। सार्वजनिक क्षेत्र में जो विस्तार की तथा दूसरी योजनायें इस समय कार्याधीन है उनमें मशीन निर्माण, वैज्ञानिक खाद और औषधियां शामिल है। भोपाल, राची और दुर्गापुर में बिजली का भारी सामान, भारी औद्योगिक मशीनें और खानो में खुदाई की मशीनें बनाने के कारखाने स्थापित किये जा रहे है। वैज्ञानिक खाद के नये कारखाने नांगल, राउरकेला और नेवेली में लगाये जा रहे हैं और सिन्दरी का कारखाना बढ़ा कर बड़ा कर दिया गया है। जिन नई योजनाओं पर कार्य हो रहा है उनमें दवाइया और एंटीबायोटिक्स तैयार करने के कारखाने शामिल हैं।

१५. गत सप्ताह मुझे राउरकेला और भिलाई के इस्पात के कारखानों का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां लोहे का उत्पादन शुरू हो चुका है। आशा है इस वर्ष के समाप्त होने से पहले इन कारखानों में इस्पात भी तैयार होने लगेगा। दुर्गापुर में भी पहली धमन भटठी इसी वर्ष चालू हो जाने की आशा है। जमशेदपुर में इस्पात के कारखाने के विस्तार का कार्यक्रम करीब-करीब पूरा हो चुका है और कुछ ही महीनों में वहां अपेक्षित उत्पादन होने लगेगा। बर्नपुर के कारखाने का विस्तार इस वर्ष के अन्त तक हो चुकेगा।

१६. कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नेवेली लिग्नाइट योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में आगे कदम उठाये गये

है। नेवेली थर्मल बिजलीघर की योजना स्वीकार कर ली गई है और इसके निर्माण का काम हाथ में ले लिया गया है।

१७. पर्यवेक्षण और ढूड खोज द्वारा भूगर्भ-विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई है और राष्ट्रीय खनिज पदार्थ निगम की स्थापना की गई है। कोयले, तांबे और जिप्सम की नई खानों का पता लगा है।

१८. तेल और प्राकृतिक गैस के लिये जोरों से खोज की गई और उसका आशाजनक फल हुआ। तेल के लिये पंजाब में ज्वालामुखी और होशियारपुर में खुदाई जारी रखी गई और आसाम में शिबसागर मे खुदाई शीघ्र ही शुरू की जायेगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना बम्बई राज्य में, कैम्बे में तेल की खोज है, जहां तेल के कई स्रोतों के मिलने की आशा की जाती है। आशा है जोरों से खुदाई के परिणाम स्वरूप इसी वर्ष कैम्बे में तेल के साधन प्राप्त हो जायेंगे। नहरकटिया तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के साधन भी मिले हैं।

१९. आसाम मे तेल साफ करने के कारखाने के निर्माण में सहायता और आवश्यक मशीनरी प्राप्त करने के लिये रूमानिया की सरकार के साथ एक समझौता कर लिया गया है।

२०. औद्योगीकरण की योजनाओं में राष्ट्रीय रसायन शालाओं ने महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने परीक्षण योजनाओं द्वारा अनुसन्धान के परिणामों को उद्योगों पर लागू कर उत्पादन में सहायता दी है। यह काम विशेष कर इस्पात के कारखानों के लिये कोयले के साधनों को उपलब्ध करने, रिफ्रेक्टरी उद्योग के लिये कच्चा माल प्राप्त करने और निजी क्षेत्र की कुछ समस्याओं को हल करने की दिशा में हुआ है। कहीं कहीं ये रसायन शालाएं आयातित सामान की जगह स्वदेशी माल का उपयोग सुझाने में सफल हुई है और घटिया किस्म के धातुओं के लाभदायक उपयोग सुझाने में भी सहायक हुई हैं।

२१. ४ मार्च १९५८ के वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अन्तर्गत उद्देश्यों पर अमल करने की दिशा में मेरी सरकार ने कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय रसायन शालाओं और उद्योग में पारस्परिक सम्पर्क है। रसायन शाला ट्रेनिंग कोर्सों, अनुसन्धान के लिये अनुदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ट्रेनिंग प्राप्त विज्ञानवेत्ताओं के उपलब्ध रहने से इस सम्पर्क को दृढ़ता तथा व्यापकता मिली है। यह निश्चय किया गया है कि दुर्गापुर में मैकेनिकल इन्जीनियरिंग के विकास और अनुसंधान के लिये और नागपुर में सार्वजनिक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय रसायन शालाएं स्थापित की जायें।

२२. सोवियत रूस और युनेस्को की सहायता से इस वर्ष बम्बई में और जर्मनी के संघीय गणतन्त्र की सहायता से मद्रास में एक एक उच्च टैक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट खोला जायेगा। इंग्लैंड की सहायता से दिल्ली में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जा रहा है। इस कालेज की नींव परमश्रेष्ठ प्रिन्स फिलिप एडिनबरा के ड्यूक ने अपनी हाल की यात्रा के समय रखी थी।

२३. संसद् द्वारा स्वीकृत व्यय की सीमा में, कार्य-सम्बन्धी और वित्तीय अधिकारों से सम्पन्न एक नया एटामिक एनर्जी कमीशन स्थापित किया गया है। केवल शान्तिपूर्ण कामों में उपयोग के लिये आणविक शक्ति के विस्तार तथा प्रगति के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई और हो रही है। इस दिशा में हमारे आयोजन का ध्येय उन मौलिक चीजों का उत्पादन है जिनका उपयोग चालन के लिये आणविक शक्ति को उपलब्ध करना हो। न्यूक्लीयर शक्ति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आयोजन तीसरी योजना के अन्तिम वर्षों में ही हो सकेगा, किन्तु मेरी सरकार ने न्यूक्लीयर शक्तियुक्त

कारखाने स्थापित करने का फैसला किया है जिनमें कम से कम २५० हजार किलोवाट की बिजली पैदा की जायेगी।

२४. गत वर्ष मैंने अपने भाषण में आपसे कहा था कि रिएक्टर्स के लिए एटामिक विशुद्धता और ईधन पदार्थ युक्त युरेनियम धातु का उत्पादन चालू वर्ष के अन्त तक आरम्भ हो जायेगा। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि युरेनियम धातु का कारखाना बन चुका है और उसका आवश्यक परीक्षण भी हो चुका है। एटामिक दृष्टि से बिशुद्ध युरेनियन धातु के प्रथमा ढेले का उत्पादन ३० जनवरी, १९५९ को हुआ। ईंधन पदार्थ के पैदा करने की सुविधायें जुटाने का काम भी अब बहुत आग बढ़ चुका है।

२५. बहुमुखी नदी घाटी योजनाओ का काम भी निर्धारित समय के अनुसार इस वर्ष आगे बढ़ा है। बाढ़ नियन्त्रण के लिये नियुक्त उच्चाधिकार-सम्पन्न समिति की रिपोर्ट मेरी सरकार के विचाराधीन है।

२६. कलकत्ता के और मद्रास के बन्दरगाहों के सुधार के लिए २० करोड़ रुपये लगेंगे, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों ने विश्व बैंक के साथ बातचीत कर वित्तीय समझौते किये है।

२७. मेरी सरकार स्वेच्छा से और समझौते के आधार पर दोनों रूप से औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने और बढ़ाने के प्रयत्न में सफल हुई है। एक अनुशासन नियमावली जो दोनो ओर के मालिक और मज़दूरों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की मान्यता की आवश्यकता पर जोर देती है, मालिक और मज़दूरों की सभी केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। इस नियमावली में व्यवहार के नियम बताये गये है। इसमें बताया गया है कि किसी भी ओर से एक-तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिये, हड़ताल और कामबन्दी से बचना चाहिये और झगड़ों के बीच बचाव तथा निपटारे के लिये जो साधन हों, वे तुरन्त काम में लाये जाने चाहियें। नियमावली यह भी बताती है कि अपने अपने दोषी सदस्यों के प्रति मज़दूर और मालिक संस्थाएं क्या अनुशासन रखें। श्रमसम्बन्धी कानूनो और निर्णयों की कहां तक अवहेलना हुई है, यह देखने के लिये और उन नियमों तथा निर्णयों को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिये एक त्रिदलीय समिति बनाई गई है। एम्प्लौईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम, जिसमें करीब-करीब चौदह लाख मज़दूर शरीक हैं, अब और अधिक लोगों पर लागू की जा रही है। संचालन-कार्य में मज़दूरों को हिस्सा देने की दिशा में कदम उठाया गया है और अब निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कतिपय उद्योगों के लिए संयुक्त समितियां स्थापित की गई है।

२८. आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई, है जिसके फलस्वरूप मेरी सरकार विदेशी मुद्रा में बचत कर सकी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान और विकास तथा इसके लिए सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी कदम उठाये गये हैं। प्रतिरक्षा के साधनों के निर्माण के लिए आवश्यक माल और साधन की उपलब्धि की दिशा में कुछ प्रगति है।

२९. अनुच्छेद ३४४ के अनुसार भाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसद् के सदस्यों की जो समिति नियुक्त की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। चालू सत्र में उस पर विचार करने का आपको अवसर मिलेगा।

३०. नागा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हिंसा और अराजकता की वारदातों में बहुत कमी हुई है। नागा लोगों ने साधारण तौर से मेरी सरकार की नीति को पसन्द किया है। मई १९५८ में अखिल जन-जाति सम्मेलन में अगस्त, १९५७ में हुए कोहिमा सम्मेलन के निर्णयों का अनुमोदन किया। बहुत से नागा लोग जो

वरोधी दल में थे और लुक-छिप कर आन्दोलन चला रहे थे, अब शान्तिपूर्ण ढंग से जीवन, यापन कर रहे हैं ।

३१. सिक्किम विकास योजना, जिसका खर्चा भारत वहन करता है, ठीक ढंग से चल रही है । गंगटोक से नाथूला तक सड़क तैयार हो गई है और यातायात के लिए खुल गई है । यह सड़क बहुत ही दुस्तर पहाड़ियों से होकर गुजरती है और इसके निर्माण के लिए हमारे इंजीनियर बधाई के पात्र हैं । ६०० मील लम्बी सड़क बनाने के लिये गत वर्ष जनवरी में नेपाल, अमेरिका और भारत के बीच एक त्रिदलीय समझौता हुआ था । त्रिसूली-जल-विद्युत् योजना के निर्माण के लिये एक और समझौता किया गया और योजना पर काम जारी हो गया है । यह योजना काठमांडू घाटी के लिये १२ हजार किलोवाट बिजली पैदा करेगी ।

३२. पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों के पुनःसंस्थापन के काम में काफी उन्नति की जा चुकी है । जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए लोगों का सम्बन्ध है, आशा की जाती है कि पुनःसंस्थापन का अन्तिम काम अर्थात् क्षतिपूर्ति की अदायगी इस वर्ष के भीतर समाप्त हो जायेगा । पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों में से करीब ६० हज़ार पिछले वर्ष शरणार्थी शिविरों से पुनर्वास के स्थानों में पहुंचा दिये गये । यह फैसला किया गया है कि इस वर्ष जुलाई के अन्त तक पश्चिमी बंगाल में सभी शिविर बन्द कर दिये जायें । हमें आशा है कि बाकी ३५ हज़ार विस्थापित परिवार उस समय तक या तो काम और पुनःसंस्थापन के लिये दण्डकारण्य में जा बसेंगे या दूसरे राज्यों में नियत बस्तियों में जा चुकेंगे ।

३३. गैर-सैनिक अनुमानित व्यय के बजट और वित्तीय नियन्त्रण के सम्बन्ध में जो व्यवस्था थी, उसमें सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं । विकास-योजनाओं को अधिक तेजी से कार्यान्वित करने की दृष्टि से प्रशासनिक मन्त्रालयों को अधिक व्यापक वित्तीय अधिकार दिये गये हैं, जिससे कि वे वित्त मन्त्रालय द्वारा संशोधित और बजट में शामिल की गई मदों पर व्यय की स्वीकृति स्वयं दे सकें ।

३४. संसद् के गत सत्र के बाद एक अध्यादेश, "दि इन्डियन इन्कमटेक्स (एमेन्डमेन्ट) आर्डिनेन्स १९५९", जारी किया गया । इस अध्यादेश से सम्बन्धित एक विधेयक संसद् के सामने रखा जायेगा ।

३५. १९५८ में संसद् द्वारा ४९ विधेयक पारित किये गये । तेरह विधेयक आपके विचाराधीन हैं । विधेयकों और संशोधनों के रूप में मेरी सरकार कई वैधानिक प्रस्ताव संसद् के समक्ष रखना चाहेगी । उनमें ये प्रस्ताव शामिल हैं :—

(१) दि कम्पनीज़ (एमेन्डमेंट) बिल ।

(२) एस्टेट ड्यूटी (एमेन्डमेन्ट) बिल ।

(३) दि स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सब्सीडियरी बैंक्स) बिल ।

(४) दि कोल माइन्स लेबर वेलफेयर फंड (एमेन्डमेन्ट) बिल ।

(५) दि आल इण्डिया मेटरनिटी बैनिफिट बिल ।

(६) बिल टू प्रोवाइड फार कम्पलसरी नोटिफिकेशन आफ वेकेन्सीज बाई एम्पलोयर्स टू एम्पलोयमेन्ट एक्सचेंजिस ।

(७) दि जिनेवा कनवेन्शन बिल ।

(८) दि सेविंग्स बैंक (एमेन्डमेन्ट) बिल ।

(९) दि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (एमेन्डमेन्ट) बिल ।

(१०) दि चिल्ड्रन बिल ।

(११) ए बिल फार दि प्रीवेंशन आफ क्रुएलटी टू एनीमल्स ।

३६. १९५९–६० वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार के आय व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सामने रखे जायेंगे।

३७. संसार में तनाव की भावना अभी बनी है और स्थिति में आधारभूत सुधार के लक्षण अभी दिखाई नहीं देने लगे है, यह मेरी सरकार के लिये चिंता का विषय है। मेरी सरकार बड़े राष्ट्रों के प्रति तटस्थता की नीति का बराबर अनुसरण कर रही है और तदनुसार तनाव को दूर करने के काम में यथासम्भव योगदान दे रही है।

३८. विज्ञान और टैकनौलोजी में महान् प्रगति के कारण मानव ने अन्तर्नक्षत्रीय आकाश के समन्वेषण का साहस किया है और इसके फलस्वरूप मानवीय उन्नति की कल्पनातीत सम्भावनायें सामने आयी है। अन्य राष्ट्रों के साथ मेरी सरकार भी इस बात से चिन्तित है कि विज्ञान की यह प्रगति अभी तक अधिकतर ऐसे विध्वंसात्मक शस्त्रों के बनाने में ही काम में लाई गई है, जिनसे संसार के विनाश का संकट पैदा हो गया है।

३९. मेरी सरकार को इस बात का खेद है कि जहां एक ओर न्यूक्लीयर और थर्मोन्यूक्लीर विस्फोटों पर रोक लगाने की दिशा में जिनेवा में कुछ प्रगति हुई है, वहां दूसरी ओर इसके बारे में और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या अर्थात् निःशस्त्रीकरण और विनाश के इन अस्त्रों पर रोक लगाने की दिशा में, समझौता तो एक तरफ, सच्ची प्रगति भी अभी दिखाई नहीं दी है।

४०. पिछले साल सितम्बर में मेरे प्रधान मन्त्री ने उस समय के पाकिस्तानी प्रधान मन्त्री के साथ सीमावर्ती इलाकों के सम्बन्ध में कुछ समझौते किये थे। पाकिस्तान में स्थित कूचबिहार के कुछ इलाकों और भारत में स्थित कुछ पाकिस्तानी इलाकों का विनिमय भी इन समझौतों में शामिल था। इन समझौतों को कानूनी रूप देने के लिये मेरी सरकार आपके सामने प्रस्ताव रखेगी।

४१. दूरस्थ और निकट के देशों से हमारे सम्बन्ध बराबर मैत्रीपूर्ण रहे।

४२. जापान के सम्राट के निमन्त्रण पर सितम्बर, १९५८ के अन्त में मैंने उस देश की यात्रा की और जापान के सम्राट् तथा लोगों ने मेरा हार्दिक स्वागत किया।

४३. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और मलाया के सर्वोच्च शासक के निमन्त्रणों पर गत दिसम्बर, १९५८ में मैंने उन देशों की यात्रा की और दोनों ही देशों की सरकारों तथा जनता ने उदारतापूर्वक मेरा स्वागत किया।

४४. गत वर्ष सितम्बर में मेरे प्रधान मंत्री ने भूटान की यात्रा की, जिससे हमारा एक विशेष संधिगत सम्बन्ध है। वहां के शासक तथा लोगों ने उनका स्नेहपूर्ण स्वागत किया। प्रधान मंत्री ने उन्हें भारत और भूटान के बीच स्थायी मैत्री का आश्वासन दिया और यह कहा कि वहां के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का हमारा संकल्प है। हम आशा करते हैं कि भूटान और भारत के बीच यातायात के साधनों में सुधार के फलस्वरूप दोनों जगह के लोग एक दूसरे के और निकट आ जायेंगे।

४५. सूडान, ईराक, गिनी और क्यूबा में नई शासनसत्ताओं के स्थापित हो जाने पर मेरी सरकार ने उन्हें राजनयिक मान्यता प्रदान की।

४६. पिछले वर्ष हमें अपने सम्मानित अतिथियों के रूप में महामहिम अफ़गानिस्तान के सम्राट्, महामहिम नेपाल सम्राट् तथा साम्राज्ञी, वियतनाम के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपति, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, न्यूज़ीलैंड, टर्की, कम्बोदिया, पाकिस्तान, कनेडा, घाना, नार्वे, रूमानिया और अफ़गानिस्तान के प्रधान मंत्रियों, अर्थशास्त्र के जर्मन संघीय मंत्री, संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी

प्रतिनिधि-मंडल के अध्यक्ष, श्री हैनरी केबट लाज, और एडिनबरा के ड्यूक के स्वागत करने का श्रेय प्राप्त हुआ ।

४७. वियतनाम और कम्बोदिया में देखरेख और नियंत्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन आलोच्य वर्ष में कार्य करता रहा, किन्तु लाओस मे कमीशन ने अनिश्चित काल तक के लिए अपनी कार्यवाही स्थगित की और यह निश्चय किया कि साधारण प्रणाली के अनुसार इसे फिर से बुलाया जा सकता है । मेरी सरकार को इस बात का खेद है कि लाओस में स्थिति और अधिक बिगड़ गई है और सुधार की जो आशा मैंने पिछले साल प्रकट की थी, वह पूरी नहीं हुई । फिर भी मेरी सरकार का बराबर यह विश्वास है कि जेनेवा समझौते से जो शान्ति वहां स्थापित हुई है,वह बनी रहेगी और अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के सदस्य एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग करते रहेंगें और शान्ति-स्थापना के हित में लाओस की सरकार का सहयोग भी उन्हें मिलता रहेगा ।

४८. भारत ने लेबनान स्थित संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षण दल में भाग लिया और उस क्षेत्र में एक संकटापन्न स्थिति को सुलझान में अपना विनम्र योगदान दिया ।

४९. दक्षिण अफ्रीका की घटनायें, जहां की सरकार पृथक्ता की नीति का कठोरता से अनुसरण कर रही है और जिसके कारण उस देश के अधिकांश लोगों को अपमान और यातनायें सहनी पड़ रही हैं, जिनसे संयुक्त राष्ट्र के अधिकार-पत्र में दिए गए मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे लिए घोर चिन्ता का विषय हैं । किन्तु इस बात से कुछ संतोष होता हैं कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत बड़ा बहुमत इस नीति का विरोध करता है । हमारी बराबर यही आशा है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार संसार के जनमत का आदर करेगी और यह स्वीकार करेगी कि प्रबुद्ध अफ्रीका में ऐसी नीतियों का परिणाम यही होगा कि जातीय कटुता बढ़ेगी और अन्त में संघर्ष होगा, जो व्यापक हो सकता है ।

५०. भारत में गत वर्ष न्यूज़ीलैंड के उच्चायुक्त के दफ्तर की स्थापना का मेरी सरकार ने स्वागत किया है ।

५१. पिछले साल हमारे देश में कई एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए । देश के लोगों की ओर से बाहर से आने वाले महानुभावों का स्वागत और आतिथ्य कर और विश्व में सद्भावना और पारस्परिक आदान-प्रदान को उभारने में किंचिन्मात्र अपना योगदान दे सकने की मेरी सरकार को बहुत खुशी है ।

५२. संसद् के सदस्यगण, मैंने आपक सामने पिछले वर्ष की प्रमुख घटनायें तथा सफलतायें रखी है । राष्ट्रीय विकास और उन्नति के सम्बन्ध में किसी हद तक हम अपने आप को मुबारकबाद कह सकते हैं । किन्तु पहले से भी कहीं अधिक आज हमारा यह सौभाग्य और कर्तव्य है कि हम और अधिक दृढ़ता, अनुशासन और ध्येय-प्राप्ति की भावना के साथ लोकतन्त्र को सच्चे अर्थों में अपने देश के जनसाधारण के लिए वरदान बनाने का प्रयत्न क ें।

५३. मेरी सरकार की यह नीति है और वह सदा इस बात का प्रयत्न करती रहेगी कि इस पुण्य भूमि की और यहां के लोगों की स्वाधीनता तथा मान सदा सुरक्षित रहें, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक कल्याण की प्रवृत्तियों को बल मिले और ऐसी लोक-तन्त्रात्मक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो, जिसमें शान्तिपूर्ण ढंग से जनमत के बल पर उन्नति की चेष्टा और प्राप्ति की जाए ।

५४. संसद् के सदस्यगण, अब मै आप का काम आपको सौंपता हूं और आपके प्रयत्नों में आप सब की सफलता की कामना करता हूं । आपके प्रयत्न और आपकी

एकता और अन्तिम ध्येय की प्राप्ति की भावना तथा कर्तव्यपरायणता हमारे देशवासियों को अधिक सम्पन्न और संतुष्ट बनाने में, राष्ट्र के स्थायित्व और सुरक्षा को अधिक दृढ़ करने में और विश्व में शान्ति तथा सहयोग का संचार करने में सहायक हो, यही मेरी प्रार्थना है ।

(*Text of the President's Address in English*)

Members of Parliament, I welcome you once again to your labours in a new session of Parliament.

2. We are near the end of the third year of the Second Five Year Plan. In my address to you last February I drew your attention to the stresses and strains to which our economy is subject. I expressed the concern of my government that our temporary difficulties should not lead us in the direction of retarding development and progress. Difficulties should be overcome by reconsideration and revision of methods and by planned mobilisation of resources.

3. In May, and again in November 1958, the National Development Council took into consideration the problems of resources, of production and of phasing relevant to the Second Plan and decided that the Plan outlay should be Rs. 4,500 crores and this total should be reached by conservation of and addition to resources.

4. The economic policy of my Government has this end in view. Measures have been adopted to limit and phase foreign exchange commitments and expenditure, to arrest rise in internal prices and to increase foreign earnings. Export duties on a number of commodities have been reduced or abolished and export quotas have been liberalised. In August 1958, as a result of a comprehensive review of regulations, export control was removed from as many as 200 commodities and the number of commodities subject to quota restrictions severely curtailed.

5. My Government have made successful attempts to secure foreign assistance by way of aid and loans to tide us over our temporary difficulties. Negotiations for further aid are in progress. Aid or loans from foreign countries for which my Government and our people are duly grateful are not governed by the attachment of any political conditions to them. Negotiations in regard to future assistance will also be on the same basis.

6. Our Second Plan is only part of the whole process of planned development of our economy. The steps we now take are but stages along the long and arduous road to planned prosperity and my Government, through the Planning Commission, have already initiated consideration and studies of the Third Plan. It is hoped that by the end of the Third Plan, a sound foundation will have been laid for future progress in regard to our basic industries, agricultural production and rural development, thus leading to a self-reliant and self-generating economy.

7. Planning is a national undertaking requiring the efforts of the whole nation and the co-operation of all at every stage. My Government have therefore called for, and look forward to a constructive, even if critical, approach by all and contribution in ideas from the different shades of opinion in Parliament and outside. To this end, my Prime Minister and the Planning Commission are seeking the co-operation of all parties.

8. It is proposed to prepare a preliminary Draft Outline or Plan Frame for the Third Plan by the end of this year. After the preliminary Draft Outline has been discussed and approved, detailed consideration of Central and State Plans will commence. The principal objectives which we have accepted are: a

substantial increase in national income, rapid industrialisation, expansion of employment on a sufficient scale, and a reduction in inequalities of income and wealth. The Government will continue to aid and support small and cottage industries. The tempo of development already attained must be maintained and accelerated.

9. Food and food prices are the most important factors in the regulation of our economy. On these largely depend other factors vital to our planning and progress, such as availability of foreign resources for development, the balance of payments position, the maintenance of internal price levels and the arrest of inflation, if and when it tends to set in.

10. To check the rise in prices of foodgrains, in early 1958, following failure of rains and widespread damage to crops, my Government imported 2·74 million tons of foodgrains in the first eleven months of 1958, regulated internal movement of foodgrains and made supplies available to the consumer through fair price shops. The Reserve Bank enforced its policy of restraint on availability of Bank credit for buying up of foodgrains by private parties.

11. In this respect self-sufficiency in food alone can provide a satisfactory solution. Increased yields, by greater and sustained efforts and the adoption of improved methods in agriculture combined with the necessary agrarian reforms, which would make agriculture both gainful and economic, are imperative. To this end, my Government will seek to promote agrarian reforms, Co-operation and devolution of functions to village units.

12. The crop prospects for 1959-60 are in refreshing contrast to our plight the previous year. Nature is being kinder to us this year, and the outlook both in regard to food and commercial crops is promising. We have a very good rice crop and prices of rice have already recorded a marked fall. It is intended to build up considerable stocks and to widen the scope of State trading. Wheat and gram prices have risen, but, according to present indications, the *Rabi* crop will be good. Our developmental efforts, in regard to the major crops, by intensive production campaigns, greater stress on minor irrigation projects, proper utilisation and maintenance of existing works, increased momentum in the establishment of seed farms, more promising tendencies to adopt better methods, and extension of soil conservation programmes, account in a considerable measure for the more hopeful horizon in agriculture.

13. The Community Development programme, on which largely depend the effective extension and implementation of democracy in meaningful terms to the large masses of our people, now covers 300,000 villages and roughly a rural population of 165 millions. Measures for more effective participation of the people in this vital development are being implemented. The basic unit of our democracy, the Panchayat, is being provided with increased resources and functions. Village Co-operatives are being organised and developed so as ultimately to cover the entire rural area.

14. Industrial production, as a whole, showed progress, but some industries, notably textiles, have suffered a set-back. Among the industries, both in the public and private sectors, which achieved a substantial increase in output were machine tools, penicillin, insecticides, paper and board, diesel engines, electric motors, sulphuric acid, caustic soda, tyres, sewing machines, bicycles and electric fans. New schemes of development and expansion in the public sector, which are in progress, cover machine building, fertilizers and drugs. Plants to build heavy electrical equipment, heavy industrial machinery and mining machinery are being set up at Bhopal, Ranchi and Durgapur New fertilizer plants are being established at Nangal,

Rourkela and Neyveli, while Sindri has been expanded. Projects for the manufacture of drugs and antibiotics are also among the new development schemes in progress.

15. I had the pleasure of inaugurating the two large steel plants at Rourkela and Bhilai last week, where production of pig iron has now started. It is expected that steel will be produced in these plants before the end of the year. It is also expected that the first blast furnace at Durgapur will begin to function before the end of the year. The programme of expansion of the steel plant at Jamshedpur has been almost completed and full production will be achieved within a few months. The steel works at Burnpur will complete their expansion programme by the end of the year.

16. Coal production has increased. Further steps have been taken towards implementing the Neyveli Lignite Project. The Project Report of Neyveli Thermal Power Station has been accepted and action for construction initiated.

17. There have been advances in the development of mineralogy by way of intensive surveys and exploration, and the National Mineral Development Corporation has been established. New deposits of coal, copper and gypsum have been discovered.

18. The search for oil and natural gas was intensified and has yielded promising results. Drilling for oil has been continued at Jwalamukhi and Hoshiarpur in the Punjab, and will be started soon in the Shibsagar area in Assam. The most significant development has been in the Cambay area of Bombay where oil under considerable pressure has been discovered, and there are indications of several promising oil horizons. It is hoped that by an intensive programme of test drilling, the extent of the potential oil reserves of the Cambay area will be established during this year. Considerable reserves of natural gas have also been found in Naharkatiya Oil Fields.

19. An agreement has been concluded with the Government of Rumania for the supply of equipment and assistance in the construction of an oil refinery in Assam.

20. The National Laboratories have played an important part in the plans of industrialisation. They have harnessed the results of their research to production by erection of pilot plants, particularly for the development of coal resources for the steel plants, raw materials for refractories, and in assisting the private sector in certain problems. The Laboratories have in a number of cases made possible the use of indigenous in place of imported material, and also assisted in the utilisation of low grade ores.

21. My Government have taken steps in several directions to implement the purposes contained in the Scientific Policy Resolution of the 4th of March 1958. Close liaison exists between the National Laboratories and Industry. Laboratory training courses, and grants-in-aid schemes for research promote these relations as well as the scientific approach and the availability of scientifically skilled manpower. It has been decided to establish National Laboratories for research and development in Mechanical Engineering at Durgapur and Public Health Engineering at Nagpur.

22. Two more Higher Technological Institutes will be opened this year, one in Bombay with the aid of the U.S.S.R. and UNESCO, and the other in Madras with the aid of the Federal Repubuic of Germany. A College of Engineering is being established in Delhi with United Kingdom aid. The foundation-stone of this institution was laid by His Royal Highness Prince Philip, The Duke of Edinburgh, during his recent visit.

23. A new Atomic Energy Commission, with executive and financial powers, within the limits of the expenditure sanctioned by Parliament, has been established. Considerable advance and expansion in the field of

atomic energy, and exclusively for peaceful purposes, has been made and continues satisfactorily. The aim of planning in this field is the production of all the basic materials required for the utilisation of atomic energy for power. While large-scale achievement in this field of nuclear power must await the later stages of the Third Plan, my Government have decided to install nuclear powered plants to produce electricity of a minimum capacity of 250 thousand Kilowatts.

24. In my address to you last year I said that uranium metal of atomic purity and fuel elements for the reactors will be in production before the end of the current year. I am glad to say that the construction of the uranium metal plant has been completed and has undergone trial runs successfully. The first ingot of atomically pure uranium metal was produced on January 30th 1959. The construction of the facility for producing fuel elements is also far advanced.

25. The work on the River Valley Multi-Purpose Schemes has progressed during the year according to schedule. The Report of the High Level Committee on Flood Control is under consideration of my Government.

26. The ports of Calcutta and Madras are to be improved at a cost of 20 crores of rupees, for which the Port authorities have entered into financial agreements with the World Bank.

27. My Government have met with success in their endeavours to promote industrial relations on a voluntary and agreed basis. A "Code of Discipline", which stresses the need for recognition by employers and workers of both the rights and responsibilities of either side, has been ratified by all Central Organisations of Employers and Workers. This Code also prescribes certain norms of behaviour. It provides that unilateral action by either side should not be taken, lock-outs and strikes should be avoided and the machinery for the settlement of disputes should be utilised expeditiously. The Code also prescribes sanctions to be invoked by the Workers and Employers Organisations in regard to their respective defaulting members. A Tripartite Committee has been constituted to assess the extent of the non-implementation of Labour Enactments and Awards and also to secure their proper implementation. The Employees' State Insurance Scheme, which already covers nearly fourteen lakhs of workers, is being further extended. A beginning has been made in workers' participation in management and Joint Councils have been set up in several industrial undertakings, both in the public and private sectors.

28. There has been a substantial increase in the output of the Ordnance Factories which has enabled my Government to effect appreciable savings in foreign exchange. There have also been advances in scientific and industrial research and development, and the expansion of facilities in this respect. This has enable progress in the indigenous production of the materials required for the manufacture of Defence equipment.

29. The Committee of Members of Parliament constituted in accordance with Article 344 of the Constitution to examine the recommendations of the Official Language Commission has submitted its Report. You will have the opportunity of considering it during the current session.

30. The situation in the Naga Hills shows appreciable improvement. Cases of violence and lawlessness have markedly declined. The Nagas, generally, have appreciated the policy of my Government. In May 1958 the the All-Tribal Convention reinforced the decisions of the Kohima Convention of August 1957. Large numbers of Nagas who were previously hostile and had gone underground are now pursuing normal and peaceful avocations.

31. The Sikkim Development Plan, which is financed by India, is making good progress. The road from Gangtok to Nathu La has been completed and is open to vehicular traffic. This road passes through a very difficult mountain terrain and our engineers are to be congratulated on the success of this undertaking. A tripartite agreement to which Nepal, the United States of America and India are parties for the construction of 900 miles of road was signed in January last year. An agreement for the construction of the Trisuli Hydro-Electric Project has been concluded and work begun. This Project will generate 12,000 kilowatts of electricity for the Kathmandu Valley.

32. Considerable progress has been achieved in the rehabilitation of displaced persons from Pakistan. So far as the displaced persons from West Pakistan are concerned, it is hoped that the last stage of rehabilitation, that is, payment of compensation, will be completed during this year. In regard to displaced persons from East Pakistan, about sixty thousand have moved from camps to rehabilitation sites during the past year. It has been decided to close the camps in West Bengal before the end of July this year. It is expected that the remaining thirty-five thousand displaced families will have moved by that time from the camps either for work and rehabilitation in Dandakaranya, or to rehabilitation sites in other States.

33. My Government have recently made certain important changes in regard to arrangements for budgeting and financial control over expenditure from the Civil estimates. In order to secure a speedier implementation of our development plans, the administrative Ministries have been given wider financial powers to issue expenditure sanctions to schemes which have been included in the Budget Estimates after scrutiny by the Finance Ministry.

34. An Ordinance, namely, "The Indian Income-Tax (Amendment) Ordinance, 1959", has been promulgated since the last session of Parliament. A Bill dealing with this Ordinance will be placed before Parliament.

35. Forty-nine Bills were passed by Parliament during the year 1958. Thirteen Bills are pending before you. My Government intend to introduce a number of legislative proposals both by way of new Bills and amendments. Such proposals will include:—

(1) The Companies (Amendment) Bill.

(2) Estate Duty (Amendment) Bill.

(3) The State Bank of India (Subsidiary Banks) Bill.

(4) The Coal Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill.

(5) The All-India Maternity Benefit Bill.

(6) Bill to provide for compulsory notification of vacancies by employers to Employment Exchanges.

(7) The Geneva Convention Bill.

(8) The Savings Bank (Amendment) Bill.

(9) The Banaras Hindu University (Amendment) Bill.

(10) The Children Bill.

(11) A Bill for the Prevention of Cruelty to Animals.

36. A statement of the estimated receipts and the expenditure of the Government of India for the financial year, 1959-60, will be laid before you.

37. My Government note with concern the continuance of world tensions and that basic improvements in the world situation are not yet on the horizon. My Government, however, continue to pursue their policy of non-alignment with the great Power

Blocs and of making their contribution wherever possible for the relaxation of tensions.

38. The vast advances in science and technology have enabled man to dare to explore inter-planetary space and have opened up before him great vistas which are full of possibilities for human progress. My Government share with others the concern that these great scientific developments have hitherto been used principally for the making of weapons of mass destruction which threaten the world with annihilation.

39. My Government note with regret that while some progress has been made at Geneva in regard to the termination of nuclear and thermo-nuclear explosions, neither in this nor in the more fundamental problem of the prohibition of these weapons of mass destruction or in the general field of disarmament, real progress, much less a settlement, is in sight.

40. In September last year, my Prime Minister reached agreements with the then Prime Minister of Pakistan in regard to certain border disputes and border problems. These included an agreement for the exchange of Cooch-Behar enclaves in Pakistan with Pakistan enclaves in India. My Government will place before you legislation to implement these agreements.

41. Our own relations with the countries far and near have continued to be friendly.

42. On the invitation of the Emperor of Japan, I visited Japan at the end of September 1958 and received a warm welcome from the Emperor and the people of Japan.

43. In December 1958 I paid visits to Indonesia and Malaya on the invitation of the President of Indonesia and the Paramount Ruler of Malaya. In both these countries I was accorded a generous welcome by the Government and the people.

44. My Prime Minister, in September last year, visited Bhutan with which country we are in special Treaty relationship. He met with an affectionate welcome from the Ruler and the people of Bhutan. He has assured them of our deep and abiding friendship and our determination not to interfere in their internal affairs. We may hope that improved communications between Bhutan and India will provide closer links between our two peoples.

45. My Government accorded diplomatic recognition to the new regimes in Sudan, Iraq, Guinea and Cuba soon after they were established.

46. We had the privilege of welcoming in this country as our honoured guests during the year: His Majesty the King of Afghanistan; Their Majesties the King and Queen of Nepal; the President of the Democratic Republic of Vietnam; the President of Yugoslavia; the Prime Ministers of New Zealand, Turkey, Cambodia, Pakistan, Canada, Ghana, Norway, Rumania and Afghanistan; the German Federal Minister of Economics; Mr. Henry Cabot Lodge, Head of the U.S. Delegation to the United Nations, and the Duke of Edinburgh.

47. The International Commission for Supervision and Control in Vietnam and Cambodia continued during the year. In Laos, however, the Commission adjourned *sine die* with the provision that it may be reconvened in accordance with normal procedures. My Government deeply regret that the situation in Laos has worsened and that the hopes to which I gave expression last year of a welcome development in that country have not been justified by events. My Government continue, however, to believe that the peace established by the Geneva Agreements will continue to endure and that the members of the International Commission

will co-operate fully with one another and obtain the co-operation of the Laotian Government in the maintenance of peace.

48. India participated in the United Nations Observation Group in the Lebanon and was able to make its modest contribution in the termination of a potentially grave situation in that area.

49. The happenings inside the Union of South Africa, resulting from the policy of Apartheid relentlessly pursued by the Government of the Union, inflicting suffering and indignity on the majority of the people of that country and involving the violation of human rights under the United Nations Charter, is of deep concern to us. We may, however, note with some gratification that these policies have been met with overwhelming disapproval by the United Nations. We continue to nurse the hope that the Union Government will respond to the call of world opinion and also recognise that such policies in a resurgent Africa will lead to increased racial bitterness and ultimately to conflicts which may become widespread.

50. My Government have welcomed the opening of the Office of the High Commissioner of New Zealand in India last year.

51. A number of International Conferences have been held in this country in the past year. My Government have been happy to accord the hospitality and welcome of our land and people to our visitors and to contribute in a small measure to world understanding and the mutual exchanges that arise from such meetings.

52. Members of Parliament, I have placed before you some of the main events and achievements of the past year. We have reason to congratulate ourselves to some extent in regard to our national development and progress. We have, however, even more than ever before, the duty and the opportunity to endeavour with greater determination, discipline and sense of purpose to make our democracy a reality in terms of the masses of our people.

53. It is the policy, and it will continue to be the endeavour of my Government, to seek in all possible ways to uphold the dignity and independence of our land and people and to promote our unity and social well-being and to build a democratic and socialist society, in which progress is sought and attained by peaceful means and by consent.

54. Members of Parliament, I bid you to your labours and wish you success. May your endeavours, your unity of ultimate purpose and your high sense of public duty bring increasing prosperity and contentment to our people, stability and security to our motherland, and assist to promote peace and co-operation in the world.

REFERENCE TO THE PASSING AWAY OF SHRI SOMNATH P. DAVE AND SHRI OSMAN SOBHANI.

MR. CHAIRMAN: I have to draw your attention to the passing away of Shri Somnath P. Dave who had a very unfortunate and sudden death. He took a good deal of interest in trade-union activities, and he also served on the Ahmedabad Municipal Council and the Gujarat University. He was a Member of the Bombay Legislative Assembly too—a man of varied interest, administrative capacity and a very high sense of duty. We are greatly saddened by his death.

I have also to refer to the passing away of a former Member of our House, Shri Osman Sobhani. He had been a regular Congress worker from the year 1921 and took a leading part in the non-cooperation movement. A very good and congenial Member of our House, he also suddenly took ill and died.